

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति०संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या: 20/2019/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

तारीख दायरा: 24.1.2019

अन्तर्गत धारा: 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

नाथूलाल आत्मज कन्हैयालाल उर्फ काना माता छोटी बाई जाति लश्करी निवासी पाचडा की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा-राज०।

...अपीलांत

बनाम

1. नारायण आत्मज गिरधारी जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. देवीलाल आत्मज भीमा जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. भवंरलाल आत्मज नन्दा जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. भूरीबाई पुत्री भीमा पत्नी रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) मृत्यु दिनांक 17.7.2018
- 4/1-किशोरी लाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
- 4/2-फुलचंद पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
- 4/3-कनफुल पुत्री भूरीबाई पत्नि चौथमल निवासीगण गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 4/4-राजबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी पूरणमल नि० जगन्नाथ सरपंच के पास नयानोहरा तह. लाडपुरा जिला कोटा
- 4/5-चतरू बाई पुत्री भूरीबाई पत्नी नन्दलाल निवासी आमा की झोपडिया अमलसरा पलायथा जिला बांरा राज०।
- 4/6-मृतक प्रभूलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 4/6/1-छोटीबाई पत्नी स्व० प्रभूलाल निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 4/6/2-सुनीता पुत्री प्रभूलाल पत्नी सुरेश निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
- 4/6/3-चयन्तीलाल पुत्र स्व० प्रभूलाल निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
- 4/6/4-गुडडी बाई पुत्री स्व० प्रभूलाल पत्नी मुकुट नि० रघुवीरपुरा पो. पनवाड तह. खानपुर जिला झाला।
5. श्रवणीबाई पुत्री भीमा पत्नी किशनलाल जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
6. घोंसी पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी डैन के पास ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
7. रेखा पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी हेण्ड पम्प के पास बस्ती आमा तहसील अन्ता जिला बांरा।
8. छोटू आत्मज मन्ना जाति लश्करी
9. घांसी आत्मज मन्ना जाति लश्करी
10. चम्पाबाई पुत्री मन्ना जाति लश्करी
11. पप्पू माता बच्ची बाई नाना मन्ना जी
12. धनराज माता बच्ची बाई नाना मन्ना जाति लश्करी निवासीगण किशनपुरा तकिया तह० लाडपुरा जिला कोटा।
13. राज० सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोजेन्ट



उपस्थित :

- श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रामप्रसाद वर्मा अभिभाषक रेस्पोजेन्ट कम-1
श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक रेस्पोजेन्ट कम-2
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोजेन्ट
श्री जगदीश खण्डेलवाल अभि० रेस्पोजेन्ट कम-4/1ता 4/5 व4/6/1ता 4/6/4 एवं 5 ता 12

:::निर्णय:::


दिनांक 24.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 142/2015 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बचनवान नाथूलाल बनाम नारायण वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट में इस न्यायालय में पेश की गई।

1 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि अपीलार्थी ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 30.4.1990 को नामा 0 सं 25 ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा में " मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व वसीयतनामा अनुसार मृतक के 1/2 हिस्से पर क्रेता की खातेदारी स्वीकार है। शास्ती के रु 5/-" बावत पारित आदेश की अप्रसन्नता से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में राज 0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस आशय की पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना व कब्जे की रिपोर्ट लिये बिना ही फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 11.1.1990 के आधार पर रेस्पो 0 क्रम-1 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। ग्राम हाथीखेडा की भूमि में भीमा के 1/3 हिस्से की भूमि पारी बाई बेवा के नाम गलत रूप से दर्ज हुई इसके बाद पुराने ख 0 नं 187 की 11 बीघा 6 बिस्वा में सेटलमेंट कार्य किया गया बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 234 की 1.80 है 0 कायम किये गये दौरान सेटलमेंट रेस्पो 0 नं 1 ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 11.1.90 जो चतुर्भुज आ 0 नन्दा, पारी बेवा भीमा व अपीलांत नाथूलाल द्वारा लिखा जाना बताया के आधार पर 1/2 हिस्से पर मिली भगत कर अपना नाम दर्ज करवा लिया जो सर्वथा गलत है क्योंकि उक्त विक्रय पत्र फर्जी व बनावटी है अपीलांत व अन्य खातेदारान ने कभी कोई ख 0 नं 234 की भूमि का बेचान नहीं किया इस कारण तथाकथित विक्रय पत्र से रेस्पो 0 क्रम-1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः तथाकथित व उसके आधार पर की गयी कार्यवाही अपीलांत के विरुद्ध प्रभावशून्य है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांत को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। फर्जी विक्रय पत्र की जानकारी होने पर अपीलांत ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत पेश किया जिस पर पुलिस थाना नयापुरा कोटा द्वारा एक एफआईआर नं 202/14 दर्ज की गयी जिसकी तफतीश जारी है तथा उक्त फर्जी विक्रय विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद भी पेश कर रखा है ऐसी स्थिति में इंतकाल नं 25 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामान्तरकरण 25 से उक्त वर्णित भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर हस्तान्तरण किये जाने से नामान्तरकरण को निरस्त करने के पर्याप्त विधिक आधार नहीं होने से अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को निर्णय दिनांक 13.11.2018 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील राज 0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं तथ्यों के सदा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए उनको पढ़े बगैर अपीलांत की अपील को खारिज करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करने में ज्युडिशियल माईन्ड एप्लाई नहीं किया। मात्र विक्रय पत्र के आधार पर अपील खारिज की गई बल्कि विक्रय पत्र के फर्जी बनावटी होने व उसकी वैधता पर गौर नहीं कर त्रुटि की है। कुटरचित, फर्जी, बनावटी तरीके से तैयार विक्रय पत्र के आधार पर नामा 0 खोला गया है जो कानूनन शुरु से प्रभाव शून्य है तथा प्रभाव शून्य विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसी स्थिति में निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांत द्वारा ग्राम भौरा से अपनी माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा तैयार किया करवाया गया तथा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के तहत किसके द्वारा इंतकाल नं 3 खुलवाकर अपीलांत का नाम खाते में दर्ज करवाकर अपीलांत के नाम से फर्जी कुटरचित व बनावटी विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर अपीलांत की उक्त भूमि को हडप करने का प्रयास किया गया है जो कि फर्जी कृत्य के तहत प्रभाव शून्य विक्रय पत्र से जो नामा 0 सं 25 दर्ज किया गया है हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलांत स्वीकार न कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा दिनांक 13.11.2018 व आदेश तहसीलदार लाडपुरा दिनांक 30.4.1990 इन्तकाल संख्या 25 ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा खारिज किया जाकर तत्समय दर्ज खातेदारों का नाम नियमानुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो 0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांत के परिवार की पैतृक कृषि भूमि ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा में पुराने ख 0 नं 187 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल ख 0 नं 234 रकबा 1.80 है 0 स्थित है। पारिवारिक सजरे अनुसार बालाजी के तीन पुत्र भीम, नन्दा, मन्ना थे तथा भीमा की मृत्यु के पश्चात उनके तीन पुत्रिया छोटी, भूरी व श्रवणी व एक बेवा पारीबाई थी भीमा के कोई पुत्र नहीं था तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी को गोद भी नहीं लिया। अपीलांत मृतक छोटी का पुत्र है। रेस्पो 0 ने गलत रूप से फर्जी मृत्यु व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भौरा से अपीलांत की मां छोटीबाई का बनाकर उसकी जगह फोती इंतकाल नं 3 से अपीलांत का नाम दर्ज कर दिया जिसकी अपीलांत को कोई जानकारी नहीं है। भूमि अपीलांत के नाम खाते में दर्ज करवाकर उक्त तथाकथित फर्जी विक्रय पत्र बनाकर अपीलांत के नाम से दूसरे व्यक्ति को खडा कर उक्त विक्रय पत्र पंजीयन करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी कर उनको पढ़े बगैर अपीलांत की अपील को खारिज करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करने में ज्युडिशियल माईन्ड एप्लाई नहीं किया। मात्र विक्रय पत्र के आधार पर अपील खारिज की गई। विक्रय पत्र के फर्जी बनावटी होने व उसकी वैधता पर गौर नहीं किया। कुटरचित, फर्जी, बनावटी तरीके से तैयार विक्रय पत्र के आधार पर नामा 0 खोला गया है जो कानूनन शुरु से प्रभाव शून्य है तथा प्रभाव शून्य विक्रय पत्र को


दिनांक 10 नवंबर 2018

किसी भी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसी स्थिति में निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। बहस में यह भी बताया कि फर्जी विक्रय पत्र की जानकारी होने पर अपीलान्त ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत पेश किया जिस पर पुलिस थाना नयापुरा कोटा द्वारा एक एफआईआर नं० 202/14 दर्ज की गयी जिसकी तफतीश जारी है तथा उक्त फर्जी विक्रय विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद भी पेश कर रखा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय एवं परीक्षण न्यायालय का इंतकाल नं० 25 निरस्त किया जावे।

- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पों क्रम-1 द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि नामा० सं० 25 दिनांक 30.4.90 की सन् 2004 में जानकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। ख० नं० 234 रकबा 1.80 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा 0.90 है० भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर अपीलान्त एवं अन्य सहखातेदार चतुर्भुज एवं पारी से दिनांक 31.3.1987 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तब से ही रेस्पों० खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्त छोटी का पुत्र है स्वयं के नाम इंतकाल तस्दीक होने के बाद विक्रय पत्र का पंजीयन स्वयं अपीलान्त द्वारा गवाहान की उपस्थिति में पंजीयन करवाया है। भूमि का बाजार मूल्य अधिक होने से अपीलान्त ने बदयान्ति पूर्वक विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में झूठे मुकदमे/इस्तगासे किये हैं। इस्तगासे में एफआर लग चुकी है न्यायालय एसडीओ एवं सिविल न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के केन्सिलेशन के मुकदमे जेरकार है। ऐसी स्थिति में सिविल कोर्ट में केन्सिलेशन का दावा जेरकार होने की स्थिति में इस अपील का कोई औचित्य नहीं है। जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपील में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत ही अपील को खारिज किया गया है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। उक्त कृषि आराजी को फर्जी मनगढन्त बनावटी एवं झूठे तथ्यों के आधार पर अपीलान्त विक्रय कर रहा है जिसके लिये अपीलान्त एवं अन्य व्यक्तियों ने उक्त कृषि आराजी के सम्बंध में किये गये बेचान के इकरारनामा एवं मुख्तारनामा को निरस्त करने के लिये दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करवाई है। अपीलान्त एवं अन्य व्यक्तियों को उक्त आराजी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी पूर्व से ही रही है इनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष वर्ष 2004 में दावा किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई थी जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया था तथा दुबारा अपीलान्त एवं अन्य पक्षकारों के मध्य दिनांक 1.4.15 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष उक्त कृषि आराजी के संबंध में की गई अपील के संबंध में राजीनामा हो गया है।
- 5 विद्वान अभिभाषक रेस्पों क्रम-2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि नाथूलाल द्वारा जो अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहा पेश की गई थी उसमें वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों से परे जाकर निर्णय पारित किया है जबकि रेस्पों० की ओर से जो पूर्व में उपरोक्त बेचान की गयी जमीन के संबंध में पुलिस में कार्यवाही की गयी थी उन कार्यवाहियों में कोई सार नहीं मानते हुये एफआर पेश कर दी थी तथा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय ने उपरोक्त विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं किया है तथा विक्रय पत्र आज दिनांक तक भी प्रभावी है और उन्ही विक्रय पत्रों के आधार पर उपरोक्त इंतकाल दर्ज किया है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पों० भूरी बाई श्रवणी घीसीबाई व अन्य द्वारा एक वाद एसीएम कोटा के यहां पेश किया था जो निरस्त हुआ उसकी अपील इनके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहा पेश की थी जिसे विज्ञो कर लिया इससे स्पष्ट है कि रेस्पों० द्वारा जो वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां पेश किया था जिसमें भी कोई सफलता नाथूलाल व अन्य को नहीं मिली तथा उसके बावजूद भी इस बिन्दू पर गौर किये बिना अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय 13.11.2018 पारित किया है वह विधि विरुद्ध है। प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रति है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय में पेश नहीं किये जा सके थे जो न्यायालय हाजा में पेश किये हैं अतः रिकार्ड पर लिया जावे। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआरपेश की थी जो न्यायालय से स्वीकार भी हो चुकी है अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। उक्त सम्पत्ति को पूर्व में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से रेस्पों० नं० 1 व अन्य बेचान कर चुके हैं तथा आ दिनांक तक बेचान प्रभावी है इसलिये अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
- 6 विद्वान अभिभाषक रेस्पों० ने बहस में बताया कि ख० नं० 234 रकबा 1.80 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा 0.90 है० भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्त एवं सहखातेदार चतुर्भुज एवं पारा से दिनांक 31.3.87 को रेस्पों० क्रम-1 ने कय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से ही रेस्पों० क्रम-1 काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्त का अपनी माँ छोटी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में जरिये फौती नामा० सं० 3 से नाम दर्ज होने उपरांत विक्रय पत्र का पंजीयन स्वयं अपीलान्त एवं चतुर्भुज एवं श्रीमति पारी की उपस्थिति में गवाहान के समक्ष करवाया है। अपीलान्त के मन में अब बदयान्ति आ जाने से उक्त आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर मुकदमे किये जा रहे हैं जिनमें से अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत झूठे इस्तगासों एफ आर लग चुकी हैं। अपीलान्त द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र केन्सिलेशन का वाद सक्षम सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है जो जेरकार है ऐसी स्थिति में अपील का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस में यह भी प्रकट किया कि विक्रय पत्र जब तक अस्तित्व में है इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में

आरआरडी 1996 पेज 587 आरआरटी 2010 (2) पेज 1317, आरआरडी 1994 पेज 520 आरआरटी 2012 (1) पेज 374 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

7 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ फर्द अहकाम न्यायालय एसीजेएम, प्रथम सूचना रिपोर्ट फौजदारी परिवाद नाथूलाल बनाम नारायण आदि, एफ.आर., एफ.एस.एल. रिपोर्ट आदि की प्रमाणित प्रतियां पेश कर उक्त दस्तावेज अपील में सुसंगत दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिये जाने बावत पेश किये गये जिसका रेस्पोंड की ओर से जवाब पेश कर आवेदन पत्र में उक्त दस्तावेज किस प्रकार सुसंगत दस्तावेज है पूर्व में किस कारण से पेश हुये थे, कारण अंकित नहीं होने से आवेदन पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज करने का अनुरोध किया। प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रकरण में प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपीयां हैं जो अपील के निर्णय में सहायक होने से प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर न्यायहित में दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं० 25 दिनांक 30.4.1990 विक्रय पत्र के आधार पर हस्तान्तरण की गई भूमि का परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरण को अपीलांत द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी बनावटी व कुटरचित है जिसकी अपीलांत को कोई जानकारी नहीं है तथा अपीलांत के नाम से दूसरे व्यक्ति को खडा कर उक्त विक्रय पत्र पंजीयन करवा लिया ऐसी स्थिति में नामा० सं० 25 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को नामान्तरकरण को निरस्त करने का पर्याप्त विधिक आधार नहीं होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 से निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया गया। प्रश्नगत द्वितीय अपील प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि "प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी कर उनको पढे बगैर अपीलांत की अपील को खारिज करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करने में ज्युडिशियल माइन्ड एप्लाई नहीं किया। मात्र विक्रय पत्र के आधार पर अपील खारिज की गई। विक्रय पत्र के फर्जी बनावटी होने व उसकी वैधता पर गौर नहीं किया। कुटरचित, फर्जी, बनावटी तरीके से तैयार विक्रय पत्र के आधार पर नामा० खोला गया है जो कानूनन शुरु से प्रभाव शून्य है तथा प्रभाव शून्य विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं होती है"। अपीलार्थी के तर्क के संबन्ध में पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित आराजी ग्राम हाथीखेडा का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं० 25 दिनांक 30.4.1990 से हस्तान्तरण किया गया है। विक्रय पत्र जब तक अस्तित्व में है इन्तकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रश्नगत अपील प्रकरण में विक्रय पत्र कुटरचित व फर्जी होने से प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने का अपीलांत का तर्क है उक्त विवादक का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है अपीलांत इसके लिये विधि अनुसार चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता बल्कि नामान्तरण कार्यवाही में भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा तय किया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्यों का परीक्षण कर उक्त वर्णित भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर हस्तान्तरण किये जाने से नामान्तरकरण को निरस्त करने के पर्याप्त विधिक आधार नहीं होने से अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को निर्णय दिनांक 13.11.2018 से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांत सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० संभागीय आयुक्त
जिला कौटा